

**Answers to the questions from Sr. No. 1 to Sr. No. 21 are obtained in an interview with  
Shri Vivek Kumar, Additional Commissioner, GST, Government of U.P. held on 16<sup>th</sup>  
July, 2016 by Mr. D.S.Verma, Executive Director- IIA & Editor IIA News.**

**1— प्र०— वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्या है ?**

**उ०—**यह वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला कर है। जिसमें वर्तमान में लग रहे वैट, प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर, सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी आदि कर विलीन हो जाएंगे। इससे व्यापारी के अधिकतर कर सम्बन्धी कार्य एक ही जगह हो जाएंगे। इसके तीन प्रकार होंगे—SGST,CGST तथा IGST । इसमें SGST तथा CGST प्रत्येक प्रान्तीय बिक्री पर लगेगा जबकि IGST केवल विक्रेता तथा खरीदार के अलग—अलग राज्य में स्थित होने पर लगेगा।

**2— प्र०—जी०एस०टी० के मुख्य बिन्दु क्या है ?**

**उ०—A—** वर्तमान में वस्तुओं के निर्माण, पर केन्द्र सरकार सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी लेती है जबकि उनकी बिक्री पर राज्य सरकार वैट आदि लेती है तथा सेवाओं पर केवल केन्द्र सरकार सर्विस टैक्स लेती है। जबकि जी०एस०टी० में वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर केवल एक कर जी०एस०टी० ही लगेगा।

**B-** यह शाराब तथा पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ कर सभी वस्तुओं की आपूर्ति पर लगेगा तथा कुछ सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर आरोपित होगा।

**3—प्र०—जी०एस०टी० से व्यापारी को क्या फायदा होगा ?**

**उ०—A—जी०एस०टी०** से पूरा देश एक बाजार बन जायेगा अर्थात् कर की दरें पूरे देश में लगभग एक समान होगी।

**B—**पूरे देश में जी०एस०टी० का लगभग एक जैसा कानून होगा। अतः अलग—अलग राज्यों के अलग—अलग नियमों से छुटकारा मिलेगा।

**C—**पूरा देश खुला बाजार होगा तथा केवल बिलो पर ही माल का परिवहन होगा अतः आयात घोषणा पत्र आदि समाप्त हो जाएंगे।

**D—**अभी तक व्यापारी को केवल अपने प्रदेश से खरीदे गए माल पर ही आई०टी०सी० मिलती है। जी०एस०टी० में पूरे देश में कहीं से भी माल अथवा सेवा लिए जाने पर आई०टी०सी० मिलेगी।

**E—जी०एस०टी०** के समस्त कार्य ऑनलाईन ही हो जाने के कारण व्यापारी को किसी सरकारी कार्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

**4—प्र०— जी०एस०टी० में समस्त काम ऑनलाईन करना होगा। इसे आम व्यापारी कैसे कर पाएगा ?**

**उ०—यदि व्यापारी इसे स्वयं या अपने कर्मचारी के माध्यम से कराने में समर्थ है तो वह सीधे जी०एस०टी०एन० की वेबसाइट पर जाकर कर पाएगा। यदि वह स्वयं नहीं करना चाहता तो सरकार द्वारा टैक्स रिट्न प्रिपेयरर की भी सुविधा दी गई है। जिनके माध्यम से व्यापारी अपने काम कर सकेगा। इसके अतिरिक्त सुविधा केन्द्र भी उपलब्ध रहेगें। जिनके द्वारा व्यापारी अपना समस्त कार्य करा सकेगा। अधिवक्ता, सी०ए० आदि से सहयोग लेने की पुरानी व्यवस्था भी रहेगी।**

**5—प्र०—यह कहा जा रहा है कि जी०एस०टी० में प्रत्येक व्यापारी को मासिक तीन या चार रिट्न दाखिल करने होगे?**

**उ०—यह बात सही नहीं है। सामान्य व्यापारी को केवल एक रिट्न दाखिल करना होगा जो अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होगा। व्यापारी को अपनी इनवायसवार बिक्री 10 तारीख के पहले एक बार में अथवा कई बार में ऑनलाईन जी०एस०टी०एन० पोर्टल पर दाखिल करनी होगी अथवा इसे आफॉलाईन बनाकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विक्रेता व्यापारी द्वारा दाखिल बिक्री सूची के आधार पर सिस्टम द्वारा व्यापारियों की खरीद सूची तैयार कर दी जाएगी तथा यह क्रेता व्यापारी को सिस्टम पर उपलब्ध होगी। क्रेता व्यापारी खरीद सूची को संशोधित कर सकता है, उसमें कोई छूटी हुई खरीद अंकित कर सकता है अथवा कोई खरीद उससे सम्बन्धित होने से मना कर सकता है। क्रेता व्यापारी द्वारा किए गए संशोधन की सूचना विक्रेता व्यापारी को सिस्टम से पहुंचेगी तथा वह उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। यह समस्त प्रक्रिया 17 तारीख तक पूर्ण करनी होगी तथा इसके बाद कर का भुगतान कर 20 तारीख तक रिट्न दाखिल करना होगा।**

**6—प्र०— क्या SGST,CGST,IGST का भुगतान अलग—अलग करना होगा और यदि हाँ तो किस प्रकार से ?**

**उ०—SGST,CGST तथा IGST का भुगतान ऑनलाईन जी०एस०टी० पोर्टल पर एक ही चालान से होगा जिसमें इसकी अलग—अलग मद्दें उल्लिखित होगी।**

**7—प्र०—क्या जी०एस०टी० में केवल ऑनलाईन पेमेन्ट ही हो पाएगा ? छोटे व्यापारियों को असुविधा होगी।**

**उ०— व्यापारी को डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड, RTGS/NEFT, तथा ऑनलाईन बैंकिंग द्वारा टैक्स पेमेन्ट की सुविधा होगी। व्यापारियों द्वारा छोटी धनराशि का नकद अथवा चेक से भुगतान जी०एस०टी०एन० के पोर्टल से प्राप्त टोकन न० के आधार पर बैंक के काउन्टर पर भी हो सकेगा।**

**8—प्र०— क्या वैट के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों को भी जी०एस०टी० में नया पंजीयन लेना पड़ेगा ?**

**उ०—नहीं, पूर्व में पंजीकृत व्यापारियों को जी०एस०टी० लागू होने पर छः माह हेतु अस्थायी पंजीयन जारी कर दिया जाएगा तथा इस अवधि में ही माँगी गई सूचनाए ऑनलाईन भर देने पर पंजीयन स्थायी हो जाएगा।**

**9—प्र०— क्या जी०एस०टी० हेतु पैन नं० होना अनिवार्य है ?**

**उ०—हाँ, जी०एस०टी० में प्राप्त होने वाला पंजीयन नं० GSTIN पैन आधारित ही होगा। 15 अंकों के इस नं० में दस अंक पैन (PAN) के ही हैं। अतः प्रस्तावित मॉडल जी०एस०टी० एकट द्वारा पैन होना अनिवार्य कर दिया गया है।**

**10—प्र०—जी०एस०टी० में पंजीयन की क्या व्यवस्था है ?**

**उ०—पंजीयन आनलाईन मिलेगा तथा तीन दिन में कोई कमी सूचित न किये जाने पर अपने आप मिल जाएगा।**

**11—प्र०— जी०एस०टी० में पंजीयन हेतु क्या कोई न्यूनतम टर्नओवर की सीमा है ?**

**उ०—वर्तमान प्रस्तावित मॉडल जी०एस०टी० एकट के अनुसार कोई भी व्यक्ति 9 लाख रु० (नौ लाख) का टर्नओवर हो जाने पर ही अग्रिम रूप से स्वयं को पंजीकृत करा सकता है परतु उसका कर दायित्व 10 लाख रु० (दस लाख) का टर्नओवर हो जाने के बाद ही प्रारम्भ होगा।**

**12—प्र०—यदि वार्षिक टर्नओवर जी०एस०टी० की पंजीयन सीमा से नीचे है क्या तब भी पंजीयन लिया जा सकता है ?**

**उ०—हाँ, कोई भी व्यापारी पंजीयन सीमा से नीचे होने पर भी स्वैच्छिक पंजीयन ले सकता है।**

**13—प्र०—छोटे व्यापारी जो बड़े स्तर पर हिसाब—किताब रखने में असमर्थ है, क्या उनके लिए भी जी०एस०टी० में कोई सुविधा है ?**

**उ०— हाँ, एक निश्चित टर्नओवर से नीचे के व्यापारी समाधान योजना का लाभ ले सकेंगे। जिसमें उन्हें टर्नओवर पर एक निश्चित प्रतिशत कर देकर निश्चिन्तता मिल सकेगी।**

**14—प्र०—क्या जी०एस०टी० में व्यापारी को कोई छोटी गलती करने पर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा ?**

**उ०—नहीं, प्रस्तावित मॉडल जी०एस०टी० एकट के अनुसार यदि किसी व्यापारी द्वारा 25 लाख रु० से अधिक की करापवचना का सम्पूर्ण साक्ष्य है तभी ऐसा किया जा सकेगा तथा इसके लिए भी कमिशनर की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।**

**15-प्र०-क्या जी०एस०टी० में भी प्रतिवर्ष कर निर्धारण होगा ?**

उ०-जी०एस०टी० में पूर्णतया स्वः कर निर्धारण की व्यवस्था लागू है तथा यदि जांचोपरान्त किसी व्यापारी के विरुद्ध कोई साक्ष्य पाया जाता है तभी उस पर किसी कर निर्धारण की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी। कुछ व्यापारियों को रिस्क पैरामीटर के आधार पर ऑडिट के लिए चिन्हित किया जाएगा।

**16-प्र०-जी०एस०टी० में कौन-कौन से कर समाहित होगें ?**

उ०- जी०एस०टी० में केन्द्र के निम्न कर समाहित होगें।

1-Central Excise duty

2-Duties of Excise (Medicinal and Toilet Preparations)

3-Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance)

4-Additional Duties of Excise (Textiles and Textile products)

5-Additional Duties of Excise (Commonly known ad CVD)

6-Special Additional Duties of Customs (SAD)

7-Service Tax

जी०एस०टी० में राज्य के निम्न कर समाहित होगें।

1-State VAT

2-Central Sales Tax

3-Luxury Tax

4-Entry Tax in lieu of octroi

5-Entertainment Tax(not levied by the local bodies)

6-Taxes on advertisements

7-Purchase Tax

8-Taxes on lotteries, betting and gambling

9-State cesses and surcharges insofar as they relate to supply of goods and services

**17-प्र०-क्या कैपिटल गुड्स पर आई०टी०सी० देय होगी ?**

उ०-कैपिटल गुड्स पर पूर्ण I.T.C.का लाभ केन्द्र सरकार के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार दिया जाएगा।

**18—प्र०—जी०एस०टी० में रिफंड की क्या व्यवस्था की गई है ?**

**उ०—रिफन्ड आवेदन के लिए समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है। दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ आनलाईन रिफन्ड आवेदन होगा तथा रिफण्ड बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवेदक के बैक खाते में जाएगा। रिफन्ड पर आवेदन प्राप्ति के 90 दिनों के अन्दर निर्णय ले लिया जाएगा अन्यथा ब्याज देय है।**

**19—प्र०—क्या रिफंड के मामले में निर्यातकों को कोई अतिरिक्त सुविधा दी गई है?**

**उ०—इन मामलों में रिफन्ड आवेदन पर 80% का भुगतान अस्थायी तौर पर बिना प्रमाणों के सत्यापन किए ही कर दिया जाएगा।**

**20—प्र०— जी०एस०टी० में निर्यातकों को क्या सुविधाएं उपलब्ध होगीं ?**

**उ०—निर्यात पर करदेयता शून्य होगी परन्तु पूर्व खरीदों पर आई०टी०सी० अनुमन्य होगी तथा इस आई०टी०सी० को प्रत्येक टैक्स पीरियड में रिफंड किया जाएगा।**

**21—प्र०—जी०एस०टी० में ई—कामर्स के लिए क्या प्राविधान किए गये हैं ?**

**उ०—ई—कामर्स कम्पनियों द्वारा अपने ऑनलाईन प्लेटफार्म से की जा रही आपूर्ति पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर स्रोत पर ही कर कटौती कर ली जाएगी किन्तु वास्तविक कर देयता विक्रेता व्यापारी पर ही होगी।**